



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 11, 2011/माघ 22, 1932

No. 73]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 11, 2011/MAGHA 22, 1932

गृह मंत्रालय

(सी एस प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 84(अ).—कैदी सम्प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 (2003 का 49) की धारा 3 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के उपबंध ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के संबंध में लागू होंगे और भारत गणराज्य की सरकार तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच हुई संधि के पाठ को निम्न प्रकार अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

दण्डित व्यक्तियों के अन्तरण के संबंध में भारत-गणराज्य की सरकार तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच क्रारार

भारत-गणराज्य की सरकार तथा ईरान इस्लामिक गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसमें इसके बाद संविदाकार देश कहा गया है;

दण्डित व्यक्तियों का उनके स्वयं के देशों में सामाजिक पुनर्वास सुगम बनाने की अभिलाषा से; और

यह मानते हुए कि यह उद्देश्य, कोई अपराध करने के परिणामस्वरूप दोषसिद्ध और दंडित किए गए विदेशी नागरिकों को उनके स्वयं के समाज में अपनी सज़ा काटने का अवसर प्रदान करके पूरा किया जाना चाहिए;

राष्ट्रीय प्रमुखता और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्तों में विश्वास करते हुए,

निम्न प्रकार सहमत हो गई हैं :

अनुच्छेद 1

परिभाषा

इस करार के प्रयोजन हेतु :

- (क) “निर्णय” से तात्पर्य न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के किसी ऐसे निर्णय अथवा आदेश से है जिसके तहत दण्ड दिया गया हो;
- (ख) “प्राप्तकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसको दण्डित व्यक्ति सज़ा काटने के प्रयोजन से अंतरित किया जा सकता हो अथवा अंतरित किया गया हो;
- (ग) “दण्ड” से तात्पर्य किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायाधिकरण द्वारा अपने दांडिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए निर्धारित समयावधि के लिए या आजीवन के लिए स्वतंत्रता से वंचित रखे जाने का कोई दंड या उपाय है;
- (घ) “दण्डित व्यक्ति” से तात्पर्य किसी न्यायालय, जिसमें संविदाकार देशों में तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा स्थापित न्यायालय भी शामिल हैं, द्वारा पारित किसी आदेश के तहत कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति से है;
- (ङ) “अंतरणकर्ता देश” से तात्पर्य उस देश से है जिसमें उस व्यक्ति को दंड दिया गया हो जिसे अंतरित किया जा सकता है या जिसे अंतरित कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 2

सामान्य सिद्धांत

- (1) इस करार के प्रावधानों के अनुसार किसी संविदाकार देश के भू-भाग में दंडित किसी व्यक्ति को सज़ा काटने के लिए दूसरे संविदाकार देश के भू-भाग में अंतरित किया जा सकता है ताकि वह उसे दी गई सज़ा काट सके। इस संबंध में दंडित व्यक्ति इस करार के अंतर्गत अन्तरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश से ऐसे अंतरण के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर सकता है।
- (2) अन्तरण का अनुरोध, अंतरणकर्ता देश अथवा प्राप्तकर्ता देश अथवा स्वयं दंडित व्यक्ति अथवा उसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का हकदार कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है।

अनुच्छेद 3
अंतरण की शर्तें

(1) इस क्रारार के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर ही अन्तरित किया जा सकता है :

- (क) वह व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का नागरिक हो;
- (ख) निर्णय अंतिम और प्रवर्तनीय हो;
- (ग) अन्तरणकर्ता देश में दंडित व्यक्ति के विरुद्ध कोई जांच, विचारण अथवा कोई अन्य कार्यवाही लम्बित नहीं हो;
- (घ) अंतरण के अनुरोध की प्राप्ति के समय, दंडित व्यक्ति द्वारा भोगी जाने वाली शेष सज्जा की अवधि कम से कम छः माह बची हो अथवा वह आजीवन कारावास की सज्जा काट रहा हो;
- (ङ.) कि व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में जिन कृत्य अथवा गलती के लिए दंड दिया गया था, वे प्राप्तकर्ता देश में दाँड़िक अपराध हो अथवा यदि वह उसके भू-भाग अपने भू-भाग में किया जाता तो वह एक दाँड़िक अपराध होता;
- (च) दंडित व्यक्ति को सैन्य कानून के तहत किसी अपराध के लिए दंडित न किया गया हो;
- (छ) प्राप्तकर्ता देश में दंडित व्यक्ति की हिरासत को अंतरित करने से अंतरणकर्ता देश के संविधान, उसकी संप्रभुता, सुरक्षा, लोक व्यवस्था अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो;
- (ज) अंतरण के संबंध में दंडित व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो अथवा किसी भी संविदाकार देश द्वारा दंडित व्यक्ति की आयु अथवा शारीरिक या मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर, जरूरी समझे जाने पर संविदाकार देश के कानून के अनुसार उस व्यक्ति की ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहमति दी गई हो; और
- (झ) अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हों।

(2) आपवादिक मामलों में, यदि दंडित व्यक्ति द्वारा भोगे जा रहे दंड की शेष अवधि छः माह से कम हो तो भी अंतरणकर्ता और प्राप्तकर्ता देश अंतरण के संबंध में सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद 4सूचना भेजने का दायित्व

(1) यदि दंडित व्यक्ति ने दंडित करने वाले देश को इस करार के तहत अन्तरित होने की इच्छा व्यक्त की हो तो, वह देश प्राप्तकर्ता देश को निम्नलिखित सूचना तथा दस्तावेज़ भेजेगा बशर्ते कि प्राप्तकर्ता अथवा अन्तरणकर्ता देश में से किसी के भी द्वारा पहले ऐसा कोई निर्णय न लिया गया हो कि वह अन्तरण के लिए सहमत नहीं है :

- (क) दंडित व्यक्ति का नाम, लिंग और राष्ट्रीयता, जन्म तिथि एवं जन्म स्थान;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश में उसका पता, यदि कोई हो;
- (ग) उन तथ्यों का विवरण जिन पर दंड आधारित था;
- (घ) दंड की प्रकृति, समयावधि एवं प्रारंभ होने की तारीख;
- (ङ) निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा कानून के उन संगत उपबंधों की एक प्रति जिनके अंतर्गत दंडित व्यक्ति के खिलाफ दंड पारित किया गया;
- (च) दंडित व्यक्ति की कोई डाक्टरी, सामाजिक अथवा अन्य कोई रिपोर्ट, जहां वह उसके आवेदन के निपटान के लिए संगत हो, अथवा उसकी परिरुद्धता के लिए तदनुसार शर्तों पर निर्णय लिए जाने के लिए आवश्यक हो;
- (छ) कोई अन्य सूचना जिसे प्राप्तकर्ता देश सभी मामलों में अपेक्षित सूचना के रूप में विनिर्दिष्ट करे कि यह संबंधित मामलों में अंतरण की संभावना पर विचार करने के लिए जरूरी है और जिससे वह अपने कानून के अंतर्गत दंडित व्यक्ति को अंतरण के सम्पूर्ण परिणामों की जानकारी देने में सक्षम हो सके;
- (ज) अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्ति अथवा अंतरणकर्ता देश के कानून के अनुसार उसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति का अनुरोध; और
- (झ) किसी विचारण पूर्व नजरबंदी, क्षमा अथवा दंड प्रवर्तन के लिए संगत किसी अन्य तथ्य को शामिल करते हुए, एक विवरण पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि कितना दंड पूरा हो चुका है।

(2) इस करार के अधीन किसी अनुरोध पर कोई भी निर्णय लिए जाने के प्रयोजन से प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को निम्नलिखित जानकारी एवं दस्तावेज़ तभी भेजेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता या अंतरणकर्ता देश में से किसी एक देश ने पहले ही यह निश्चय कर लिया हो कि वह अंतरण से सहमत नहीं होगा :

- (क) एक विवरण अथवा दस्तावेज जो यह दर्शाता हो कि दंडित व्यक्ति प्राप्तकर्ता देश का एक नागरिक है;
- (ख) प्राप्तकर्ता देश के संगत कानून की एक प्रति जिसमें ऐसे कृत्य अथवा चूंके, जिनके कारण अंतरणकर्ता देश में दण्ड पारित किया गया है, वे प्राप्तकर्ता देश के कानून के अंतर्गत अपराध माने गए हों अथवा यदि, ऐसे कृत्य अथवा चूंके इसके भू-भाग में घटित हों, तो उसे अपराध माना जाएगा;
- (ग) विशेष रूप से इस करार के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 2 के प्रभाव के अनुसार, उस अपराध, जिसके लिए सम्बन्धित व्यक्ति को अंतरणकर्ता देश में दण्डित किया गया हो, के संबंध में प्राप्तकर्ता देश में दण्ड की अवधि एवं प्रवर्तन संबंधी किसी कानून अथवा विनियम के प्रभाव का विवरण;
- (घ) दण्डित व्यक्ति के अंतरण को स्वीकार करने के लिए प्राप्तकर्ता देश की सहमति और दंडित व्यक्ति की सज्जा के बाकी बचे हिस्से को शासित करने हेतु एक वचनबद्धता; तथा
- (ङ) कोई अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जिसे अंतरणकर्ता देश आवश्यक समझे।

अनुच्छेद 5 अनुरोध एवं जवाब

- (1) अंतरण के लिए अनुरोध लिखित रूप में, प्रस्तुत किया जाएंगे और राजनयिक माध्यम के द्वारा अनुरोधकर्ता देश के केन्द्रीय प्राधिकारी के माध्यम से प्रार्थित देश के केन्द्रीय प्राधिकारी को सम्बोधित किये जाएंगे। जवाब उन्हीं माध्यमों से सूचित किए जाएंगे।
- (2) इस अनुच्छेद के पैरा 1 के प्रयोजनार्थ, भारत के संबंध में, गृह मंत्रालय और ईरान इस्लामिक गणराज्य के संबंध में न्याय मंत्रालय केन्द्रीय प्राधिकारी होंगे।
- (3) प्रार्थित देश शीघ्रतापूर्वक अनुरोधकर्ता देश को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा कि वह प्रार्थित अंतरण के लिए सहमत है अथवा नहीं।
- (4) दोनों संविदाकार देशों में से कोई भी दण्डित व्यक्ति के अंतरण से इन्कार कर सकता है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

अनुच्छेद 6सहमति और इसका सत्यापन

- (1) अंतरणकर्ता देश यह सुनिश्चित करेगा कि इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 (i) के अनुसार अंतरण के लिए सहमति देने वाला व्यक्ति, ऐसा स्वेच्छा से तथा इसके कानूनी परिणामों की पूरी जानकारी के साथ कर रहा है। इस प्रकार की सहमति देने की प्रक्रिया को अंतरणकर्ता देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा।
- (2) अंतरणकर्ता देश, प्राप्तकर्ता देश को यह सत्यापित करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा कि सहमति, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में दी गई शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 7दंडित व्यक्तियों का सौंपा जाना

अंतरणकर्ता देश के प्राधिकारी प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारियों को दोनों देशों की सहमति के अनुसार, अंतरणकर्ता देश के क्षेत्राधिकार के भीतर निर्धारित तारीख, समय तथा स्थान पर दंडित व्यक्ति को सौंपेगा। प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश से केदी को लाने के लिए जिम्मेदार होगा तथा अंतरणकर्ता देश के भूभाग से बाहर दंडित व्यक्ति की अभिरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होगा।

अनुच्छेद 8प्राप्तकर्ता देश के लिए अंतरण का प्रभाव

- (1) प्राप्तकर्ता देश का सक्षम प्राधिकारी, न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश जैसा भी इसके राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अपेक्षित हो, के माध्यम से इस करार के अनुच्छेद 9 में दी गई शर्तों के अंतर्गत सज़ा के प्रवर्तन को जारी रखेंगे।
- (2) इस करार के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के अध्यधीन, सज़ा का प्रवर्तन प्राप्तकर्ता देश तथा उस देश के कानून द्वारा शासित किया जाएगा और सिर्फ वही देश समस्त समुचित निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

अनुच्छेद 9सज्जा का सतत प्रवर्तन

- (1) प्राप्तकर्ता देश, अंतरणकर्ता देश द्वारा यथा अभिनिर्धारित सज्जा की कानूनी प्रकृति एवं अवधि द्वारा आबद्ध होगा।
- (2) तथापि, यदि सज्जा की प्रकृति अथवा अवधि अथवा दोनों ही प्राप्तकर्ता देश के कानून से असंगत हों, अथवा इसके कानून में ऐसा अपेक्षित हो, तो वह देश न्यायालय अथवा प्रशासनिक आदेश द्वारा, सज्जा को अपने स्वयं के कानून द्वारा निर्धारित दण्ड अथवा उपाय में रूपान्तरित कर सकेगा। जहां तक इसकी प्रकृति एवं अवधि का प्रश्न है, दण्ड अथवा उपाय, यथासंभव, अंतरणकर्ता देश के अधिनिर्णय द्वारा आरोपित सज्जा के अनुरूप होगा। तथापि, यह अपनी प्रकृति अथवा अवधि द्वारा, अंतरणकर्ता देश में आरोपित की गई सज्जा में वृद्धि नहीं करेगा।
- (3) इस करार के तहत अन्तरित किसी दण्डित व्यक्ति की प्राप्तकर्ता देश में उन कृत्यों अथवा चूकों के लिए न्यायिक जांच नहीं की जाएगी अथवा उसे दण्डित नहीं किया जाएगा जिनके परिणामस्वरूप उसे दण्डित किया गया था।

अनुच्छेद 10अंतरणकर्ता देश के लिए सज्जा के समापन का प्रभाव

जब प्राप्तकर्ता देश इस करार के अनुच्छेद 13 के पैराग्राफ 1 (क) के तहत अंतरणकर्ता देश को यह अधिसूचित करता है कि दंड पूरा हो गया है, तो ऐसी अधिसूचना का आशय अंतरणकर्ता देश में उस दण्ड के निर्वहन का होगा।

अनुच्छेद 11माफी, राजक्षमा अथवा लघुकरण और निर्णय की समीक्षा

- (1) कोई भी संविदाकार देश अपने संविधान अथवा अन्य कानूनों के अनुरूप दंड की माफी, राजक्षमा प्रदान कर सकेगा अथवा दण्ड का लघुकरण कर सकेगा।
- (2) केवल अंतरणकर्ता देश ही निर्णय की पुनरीक्षा के लिए किसी आवेदन-पत्र पर निर्णय लेगा।

अनुच्छेद 12दण्ड के प्रवर्तन की समाप्ति

जैसे ही अंतरणकर्ता देश द्वारा किसी भी ऐसे फैसले अथवा उपाय की सूचना दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दंड का प्रवर्तन समाप्त किया गया हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन को समाप्त कर देगा।

अनुच्छेद 13दण्ड के प्रवर्तन संबंधी सूचना

(1) प्राप्तकर्ता देश अंतरणकर्ता देश को अधिसूचित करेगा :

(क) जब दण्ड का प्रवर्तन पूरा कर दिया गया हो; अथवा

(ख) यदि दण्ड का प्रवर्तन पूरा होने से पहले दंडित व्यक्ति हिरासत से भाग जाता है। ऐसे मामलों में, प्राप्तकर्ता देश को चाहिए कि वह कैदी की गिरफ्तारी का हर-संभव प्रयास करे ताकि वह अपने दण्ड का शेष भाग पूरा कर सके और अपने संगत कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई करे।

(2) यदि अंतरणकर्ता देश द्वारा अपेक्षित हो, तो प्राप्तकर्ता देश दंड के प्रवर्तन के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 14अभिवहन

यदि कोई भी संविदाकार देश दंडित व्यक्तियों के अंतरण के लिए किसी तीसरे देश के साथ कोई व्यवस्था करता है, तो दूसरा संविदाकार देश ऐसी व्यवस्था के अनुसरण में अपने भूभाग के जरिए अंतरित किए जाने वाले दंडित व्यक्तियों के अभिवहन को सुकर बनाने में सहयोग करेगा सिवाय इसके कि वह किसी ऐसे दंडित व्यक्ति के अभिवहन से इन्कार करे जो वहीं का राष्ट्रिक हो। ऐसे अंतरण का इच्छुक संविदाकार देश दूसरे संविदाकार देश को ऐसे अभिवहन के बारे में अग्रिम नोटिस देगा।

अनुच्छेद 15लागू

अंतरणकर्ता देश के अनन्य भूभाग में होने वाले व्ययों को छोड़कर, इस क्रार को लागू करने में आने वाले सभी व्यय प्राप्तकर्ता देश द्वारा वहन किए जाएंगे। तथापि, प्राप्तकर्ता देश, अंतरण में होने वाले सम्पूर्ण अथवा आंशिक व्यय की वसूली दंडित व्यक्ति अथवा किसी अन्य स्रोत से कर सकता है।

अनुच्छेद 16आषा

अनुरोध एवं सहायक दस्तावेजों के साथ अनुरोध प्राप्तकर्ता देश की भाषा अथवा अंग्रेजी में अनुवाद संलग्न होगा।

अनुच्छेद 17लागू होने का दायरा

यह क्रार, इसके प्रभावी होने की तारीख से पहले या बाद में लगाए गए दण्ड के प्रवर्तन पर लागू होगा।

अनुच्छेद 18संशोधन

संविदाकार देशों द्वारा सहमत, इस क्रार में कोई संशोधन अथवा आशोधन स्वयं इस क्रार के प्रभावी होने के लिए यथा स्वीकार्य प्रक्रिया का अनुकरण करने के बाद ही प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 19विवादों का निपटान

इस क्रार की व्याख्या तथा इसको लागू किए जाने के बारे में किसी विवाद का निपटान राजनयिक चैनलों के माध्यम से केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

अनुच्छेद 20अंतिम प्रावधान

- (1) यह करार, अनुसमर्थन के अध्याधीन होगा तथा अनुसमर्थन के लिखित का आदान-प्रदान करने की तारीख से प्रभावी होगा।
- (2) यह करार, किसी भी संविदाकार देश द्वारा दूसरे संविदाकार देश को करार के परिसमापन के अपने आशय की लिखित सूचना दिए जाने की तारीख से छह माह तक प्रभावी रहेगा।
- (3) किसी भी परिसमापन के बावजूद, यह करार उन कैदियों के दंडों के प्रवर्तन पर लागू रहेगा जिन्हें इस परिसमापन के लागू होने की तारीख से पहले इस करार के अंतर्गत अंतरित किया गया हो।

इस करार के साक्ष्य के रूप में, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा इस संबंध में उचित प्रकार से प्राधिकृत किए जाने पर अधोहस्ताक्षरी ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके तीनों पाठ समान रूप से अधिप्रमाणित होने के नाते, इसे ईरानी हिजरी शम्सी कलेण्डर के 18 तीर 1389 दिन के सहश दिनांक 9 जुलाई 2010 को हिन्दी, पारसी तथा अंग्रेजी भाषा की दो प्रतियों में तैयार किया गया है। व्याख्या में भत्तभेद की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

ह/-

ह/-

भारत गणराज्य की
ओर से
विदेश मंत्री
श्री एस. एम. कृष्णा

ईरान इस्लामिक गणराज्य की ओर से
आर्थिक कार्य एवं वित्त मंत्री
महामहिम डॉ. सईद शम्सीदीन हुसैनी

[फा. सं. 17011/17/2008-पी आर]

के. के. पाठक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(CS Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2011

GS.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply to the Government of Islamic Republic of Iran and notifies the text of the treaty entered into between the Government of the Republic of India and the Government of Islamic Republic of Iran as follows, namely:-

“AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS”

The Government of Republic of India and the Government of Islamic Republic of Iran hereinafter referred to as the Contracting States;

Desiring to facilitate the social rehabilitation of sentenced persons into their own countries;

Considering that this objective should be fulfilled by giving foreigners, who have been convicted and sentenced as a result of their commission of a criminal offence, the opportunity to serve their sentences within their own society; and

Believing in the principles of national sovereignty and non-intervention in internal affairs of each other,

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement:

- (a) “judgment” means a decision or order of a court or any other judicial authority imposing a sentence;

- (b) "receiving State" means a State to which the sentenced person may be, or has been, transferred in order to serve his sentence;
- (c) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court or any other judicial authority for a determinate period of time or for life imprisonment, in the exercise of its criminal jurisdiction;
- (d) "sentenced person" means a person undergoing a sentence of imprisonment under an order passed by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the Contracting States;
- (e) "transferring State" means the State in which the sentence was imposed on the person who may be, or has been transferred.

Article 2

General Principles

- (1) A person sentenced in the territory of one Contracting State may be transferred to the territory of the other Contracting State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him. To that end, he may express to the transferring State or the receiving State his willingness to be transferred under this Agreement.
- (2) Transfer may be requested either by the transferring State or the receiving State or the sentenced person himself or any other person entitled to act on his behalf.

Article 3

Condition for transfer

- (1) A sentenced person may be transferred under this Agreement only on the following conditions:
 - (a) the person is a national of the receiving State;
 - (b) the judgment is final and enforceable;
 - (c) no inquiry, trial or any other proceeding is pending against the sentenced person in the transferring State;

- (d) at the time of receipt of the request for transfer, the sentenced person still has at least six months of the sentence to serve or is undergoing a sentence of life imprisonment;
- (e) that the acts or omissions for which that person was sentenced in the transferring State are those which are punishable as a crime in the receiving State, or would constitute a criminal offence if committed on its territory;
- (f) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law;
- (g) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the Constitution, sovereignty, security, public order or any other interest of the transferring State;
- (h) consent to the transfer is given by the sentenced person or, where in view of his age or physical or mental condition either Contracting State considers it necessary, by any other person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the Contracting State; and
- (i) the transferring and receiving States agree to the transfer.

(2) In exceptional cases, the transferring and receiving States may agree to a transfer even if the remaining period to be served by the sentenced person is less than six months.

Article 4

Obligation to furnish information

(1) If the sentenced person has expressed an interest to the sentencing State in being transferred under this Agreement, that State shall send the following information and documents to the receiving State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:

- (a) the name and nationality, date and place of birth of the sentenced person;
- (b) his address, if any, in the receiving State;
- (c) a Statement of the facts upon which the sentence was based;

- (d) the nature, duration and date of commencement of the sentence;
- (e) a certified copy of the judgment and a copy of the relevant provisions of the law under which the sentence has been passed against the sentenced person;
- (f) a medical, social or any other report on the sentenced person, where it is relevant for the disposal of his application or for deciding the conditions which may accordingly be required for his confinement;
- (g) any other information which the receiving State may specify as required in all cases to enable it to consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences of transfer for him under its law;
- (h) the request of the sentenced person to be transferred or of a person entitled to act on his behalf in accordance with the law of the transferring State; and
- (i) a Statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention, remission, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence.
- (2) For the purposes of enabling a decision to be made on a request under this Agreement, the receiving State shall send the following information and documents to the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it will not agree to the transfer:
- (a) a Statement or document indicating that the sentenced person is a national of the receiving State;
- (b) a copy of the relevant law of the receiving State constituting the acts or omissions, on account of which the sentence has been passed in the transferring State, as if such acts or omissions were an offence under the law of the receiving State or would constitute an offence if committed on its territory;
- (c) a Statement of the effect of any law or regulation relating to the duration and enforcement of the sentence in the receiving State in respect of the offence for which the person concerned has been sentenced in the transferring State, particularly as to the effect of paragraph 2 of Article 9 of this Agreement;

- (d) the willingness of the receiving State to accept the transfer of the sentenced person and an undertaking to administer the remaining part of the sentence of the sentenced person; and
- (e) any other information or document which the transferring State may consider necessary.

Article 5

Requests and replies

- (1) Requests for transfer shall be made in writing and addressed through the central authority of the requesting State through diplomatic channels to the central authority of the requested State. Replies shall be communicated through the same channels.
- (2) For the purpose of paragraph 1 of this Article, the central authority shall be, in relation to India, the Ministry of Home Affairs; and in relation to Islamic Republic of Iran, the Ministry of Justice.
- (3) The requested State shall promptly inform the requesting State of its decision whether or not to agree to the requested transfer.
- (4) Either of the contracting States may refuse the transfer of sentenced person without the need for any explanation.

Article 6

Consent and its verification

- (1) The transferring State shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with paragraph 1(i) of Article 3 of this Agreement, does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the transferring State.
- (2) The transferring State shall afford an opportunity to the receiving State to verify that the consent is given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

Article 7

Handing over of sentenced persons

The handing over of the transferred person by the transferring State to the receiving State shall occur at a place to be agreed upon between the transferring and the receiving State. The receiving State shall be responsible for the transport of the prisoner from the transferring State and shall also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.

Article 8

Effect of transfer for the receiving State

(1) The competent authorities of the receiving State shall continue the enforcement of the sentence through a court or administrative order, as may be required under its national law, under the conditions set out in Article 9 of this Agreement.

(2) Subject to the provisions of Article 11 of this Agreement, the enforcement of the sentence shall be governed by the law of the receiving State and that State alone shall be competent to take all appropriate decisions.

Article 9

Continued enforcement of sentence

(1) The receiving State shall be bound by the legal nature and duration of the sentence as determined by the transferring State.

(2) If, however, the sentence is by its nature or duration or both incompatible with the law of the receiving State, or its law so requires, that State may, by court or administrative order, adapt the sentence to a punishment or measure prescribed by its own law. As to its nature and duration the punishment or measure shall, as far as possible, correspond with that imposed by the judgment of the transferring State. It shall however not

aggravate, by its nature or duration, the sentence imposed in the transferring State.

(3) A sentenced person transferred under this Agreement shall not be tried or sentenced in the receiving State for the acts or omissions on account of which the sentence was imposed.

Article 10

Effect of completion of sentence for the transferring State

When the receiving State notifies the transferring State under paragraph 1(a) of Article 13 of this Agreement that the sentence has been completed, such notification shall have the effect of discharging that sentence in the transferring State.

Article 11

Pardon, amnesty or combination and review of judgment

(1) Either of the Contracting States may grant pardon, amnesty or commutation of the sentence in accordance with its Constitution or other laws.

(2) The transferring State alone shall decide on any application for the review of the judgment.

Article 12

Termination of enforcement of sentence

The receiving State shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the transferring State of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 13

Information on enforcement of sentence

(1) The receiving State shall notify the transferring State:

- (a) when the enforcement of the sentence has been completed; or
- (b) if the prisoner escapes from custody before enforcement of the sentence has been completed. In such cases, the receiving State shall make every effort to have the prisoner arrested so that he serves the remainder of his sentence and take necessary action under its relevant law.
- (2) The receiving State shall furnish a special report concerning the enforcement of the sentence, if so required by the transferring State.

Article 14

Transit

If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the other Contracting State shall cooperate in facilitating the transit through its territory of the sentenced persons being transferred pursuant to such arrangements, except that it may refuse to grant transit to any sentenced person who is one of its own nationals. The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice to the other Contracting State of such transit.

Article 15

Costs

Any costs incurred in the application of this Agreement shall be borne by the receiving State, except costs incurred exclusively in the territory of the transferring State. The receiving State may, however, seek to recover all or part of the costs of transfer from the sentenced person or from some other source.

Article 16

Language

Requests and supporting documents shall be accompanied by a translation into the language of the requested State or into English

Article 17**Scope of Application**

This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed either before or after the entry into force of this Agreement.

Article 18**Amendments**

Any amendments or modifications to this Agreement, agreed by the Contracting States shall come into effect following the same procedure as applicable for entry into force of the Agreement itself.

Article 19**Settlement of disputes**

Any dispute regarding the interpretation and application of this agreement shall be resolved mutually by the Central authorities through diplomatic channels.

Article 20**Final Provisions**

- (1) This Agreement shall be subject to ratification and shall enter into force on the date on which instruments of Ratification are exchanged.
- (2) The Agreement shall continue to remain in force until six months from the date upon which either Contracting State gives written notice to the other Contracting State of its intention to terminate it.
- (3) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of prisoners who have been transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at New Delhi on 9th July 2010 corresponding to 18th Tir 1389 of the Iranian Hijri-Shamsi calendar, in Hindi, Persian and English languages, the three texts being equally authentic. In case of differences in interpretation, the English text shall prevail.

Sd/-

**For the
Republic of India
Minister of External Affairs
Shri S.M. Krishna**

Sd/-

**For the
Islamic Republic of Iran
Minister of Economic Affairs &
Finance
H.E. Dr. Seyed Shamseddin Hosseini**

[F. No. 17011/17/2008-PR]

K. K. PATHAK, Jt. Secy.